



कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ई.डी. की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सांसद शशि थरुर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अधीर रजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, पवन बंसल, कुलदीप इंदौरा सहित कई अन्य नेताओं को मुखर्जी नगर (नई दिल्ली) थाने ले जाया गया।

नूपुर शर्मा को मारने आया रिजवान पाकिस्तान में भी अपराधी

श्रीगंगानगर, 21 जुलाई (कास)। नूपुर शर्मा को मारने भारत आया युसुफैतिया रिजवान पाकिस्तान में इमरान सरकार को घेरने वाले कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बक से जुड़ा है। संगठन ने एक पूरा प्लान बनाकर उसे भारत भेजा था। अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस उसके लोकल कनेक्शन को तलाश रही है।

सूत्रों के मुताबिक रिजवान ने ही अगस्त 2021 में पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। इस मामले में वह जेल भी जा चुका है। श्रीगंगानगर आये एड्जीओ (सिक्योरिटी) एस. सेंगाथिर ने बताया कि 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर से लगे हिन्दुमलकोट बॉर्डर फेंसिंग से रिजवान को पकड़ा गया था। एड्जीओ का कहना है कि बिना स्थानीय मदद के इतनी बड़ी बावदात की साजिश संभव नहीं है। पूछताछ के दौरान रिजवान ने तहरीक-ए-लब्बक से जुड़े होने की बात कबुली है। अब ऐसे लोगों को ढूंढा

■ पाक घुसपैटिया रिजवान कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बक से जुड़ा है और इसी ने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी, इस मामले में वह जेल भी जा चुका है।

■ तहरीक-ए-लब्बक संगठन ने पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर रिजवान इस संगठन में शामिल हो गया था।

जा रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए इस संगठन के संपर्क में आये हैं।

जांच एजेंसियों की नजर हर उस मौसेज पर है जो पाकिस्तान से लगे बॉर्डर इलाके के लोगों को भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ पाक संगठन लोगों को भड़का रहे हैं। युसुफैतिए के पास धार्मिक किताबों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। उसके पास मोबाइल या सिम नहीं मिली है। वह बार-बार बस कहता है कि नूपुर शर्मा को मारने आया है। आरोपी खुद को 8वीं पास बता रहा है। एजेंसियों के अनुसार

वह काफी शांति है और अपने कॉन्टैक्ट के बारे में कोई भी खुलासा नहीं कर रहा है।

रिजवान का बड़ा भाई इटली और छोटा भाई दुबई में रहता है। उसका कहना है कि उसे नूपुर शर्मा का घर कहा है, इस बारे में कुछ पता नहीं था। तहरीक-ए-लब्बक संगठन ने पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर रिजवान संगठन में शामिल हो गया था। वह इस संगठन का सक्रिय सदस्य है। नूपुर शर्मा

के विवादित बयान के बाद इसी संगठन ने रिजवान को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया। संगठन की शह पर रिजवान कुछ दूर तक बस और फिर पैदल चलकर आया था। हालांकि अब तक उसने उस मदद करने वालों का खुलासा नहीं किया है।

तहरीक-ए-लब्बक पाकिस्तान में कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक संगठन है। 2018 के आम चुनाव में उसे 22 लाख से अधिक वोट

मिले थे। उसके तीन सदस्य पाकिस्तानी असेंबली में भी हैं। यह संगठन 2015 में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना खामिद हुसैन रिजवी ने की थी। उसे भारत भेजने से पहले संगठन के जिला मुख्यालय मंडी बहाउद्दीन में ट्रेनिंग देकर कासा ब्रेनवॉश किया गया था। एड्जीओ ने कहा कि तहरीक-ए-लब्बक ने युसुफैतिए को इस इलाके में प्लांट किया था वह खुद ही आया, इस बारे में साफतौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आरोपी को 23 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है।

द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की रिकॉर्ड जीत

द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वार्ता)। द्रौपदी मुर्मू (64) देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वह इस पद पर पहुंचने वाली आदिवासी समाज की पहली नेता हैं।

मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया। मतगणना के नतीजों के औपचारिक घोषणा होने से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार के खिलाफ काफी बड़ी बढ़त बना ली थी और उन्हें देशभर से बधाइयां मिलनी शुरू हो गयीं थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने देश के सुदूर पूर्वी इलाके के एक गांव में पैदा एक आदिवासी महिला को 1.3 अरब की आबादी वाले विशाल

■ इस चुनाव में मुर्मू को एन.डी.ए. में शामिल दलों के अलावा कई विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों का भी समर्थन मिला। मतगणना के रुझानों से यह झलक मिली कि, उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिला है।

■ अनुमान के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को करीब 64-65 प्रतिशत वोट मिले हैं।

लोकतंत्र के सर्वोच्च पद के लिए चुन कर आज एक इतिहास रचा है।

इस चुनाव में मुर्मू को एन.डी.ए. में शामिल दलों के अलावा कई विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों का भी समर्थन मिला। मतगणना के रुझानों से यह झलक मिली कि जनप्रतिनिधियों का उनकी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने

पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मुर्मू का समर्थन करने वाले सांसदों और विधायकों को धन्यवाद देते हुए ट्वीटर पर कहा, उनकी जीत हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मुर्मू को जीत की बधाई देने वाले पहले लोगों में थे। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में मुर्मू के निवास स्थान

पर जाकर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया और जीत की बधाई दी। विपक्ष के उम्मीदवार सिन्हा ने मतगणना की अंतिम घोषणा से पहले ही मुर्मू को जीत की बधाई दे दी थी। मुर्मू का जीवन संघर्ष पथ से शिखर पर पहुंचने की उतार-चढ़ाव भरी एक यात्रा की कहानी है। उन्होंने मयूरभंज जिले के आदिवासी गांव में जन्म लेकर जीवन के प्रारंभिक संघर्षों के बीच पढ़ाई और सरकारी नौकरी की और अध्यापन कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन 90 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, जब उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और स्थानीय निकाय में पार्षद भी चुने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को सम्पन्न हो रहा है। उनके बाद इस संवैधानिक पद और सेना के सर्वोच्च कमांडर का दायित्व मुर्मू के हाथ में होगा।

केन्द्र ने विज्ञापनों पर खर्च किये 911.17 करोड़ रु.

नई दिल्ली, 21 जुलाई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि, सरकार ने पिछले तीन सालों में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और वेब पोर्टलों में विज्ञापनों पर 911.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार व्यूरो की ओर

■ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

से विज्ञापनों का भुगतान किया गया था। ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार व्यूरो द्वारा विज्ञापनों का भुगतान किया गया था। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्यों ने सरकार से साल 2014 से वर्ष-वार और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मीडिया में विज्ञापन पर कुल खर्च का व्यौरा मांगा था।

“रीट” में डमी अभ्यर्थी बनने जा रहा अध्यापक गिरफ्तार

23 व 24 जुलाई को होने जा रही रीट परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बनने वाला आईदानाराम वरिष्ठ अध्यापक हैं

बाड़मेर, 21 जुलाई (निर्स)। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) से पूर्व बाड़मेर पुलिस ने गुरुवार को एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। यह डमी अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक हैं जो 23 व 24 जुलाई को होने वाली रीट परीक्षा में किसी और की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा देने के प्रयास में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से परीक्षा संबंधी फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि 23 व 24 जुलाई को आयोजित होने वाले रीट परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शिता पूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए पुलिस एक अभियान के अंतर्गत हल्के में निरन्तर गश्त कर रही है। इस दौरान मुखबिर से सूचना

■ पूर्व में भी वो नकल व फर्जीवाड़े के मामले में जेल जा चुका है।

■ पुलिस वास्तविक परीक्षार्थी ओम प्रकाश को भी तलाश रही है।

इस सूचना पर पुलिस टीम ने

आईदानाराम के सारण नगर स्थित किराये के कमरे में दबिश देकर चैक किया तो कमरे में रीट परीक्षा से सम्बंधित फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, ओमप्रकाश विरसोई का कूटरचित रीट परीक्षा प्रवेश पत्र व खाली स्टाम्प मिले। उसके मोबाइल फोन में भी रीट परीक्षा सम्बंधी आपतिजनक कटेन्ट मिले, जिनको बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पुलिस थाना ग्रामीण बाड़मेर में मामला दर्ज किया है। वहीं ओमप्रकाश की तलाश की जा रही है। मामले की जांच व अग्रिम अनुसंधान महिला थानाधिकारी रामप्रतापसिंह को सौंपा गया है। एएसपी दीपक भार्गव ने बताया कि आरोपी आईदानाराम पूर्व में भी नकल व फर्जीवाड़े के मामलों में जेल जा चुका है।

पचहत्तर वर्षीय सोनिया....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) करना चाहते हैं। गहलोत ने कहा, “केवल इसी उद्देश्य के चलते, प्रधानमंत्री “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की व्यवस्था लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें “उन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद “केबडिया” बॉटने में कोई समस्या नहीं चलेगी, जो उनके राजनैतिक उद्देश्यों में उनकी मदद करेंगे।

इससे पूर्व, संसद में कई विपक्षी दल सोनिया गांधी प्रतिस्पर्धन तथा हमदर्दी व्यक्त करने के लिये आगे आये। उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मीटिंग की तथा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। मीटिंग में इन पाटियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे-डी.एम.के., सी.पी.आई. (एम) सी.पी.आई., आई.यू.एम.एल., नेशनल कॉन्फ्रेंस, टी.आर.एस., एम.डी.एम. के., एन.सी.पी., वी.सी.के., शिवसेना तथा आर.जे.डी.। विपक्षी दलों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा, “मौदी सरकार ने जाँच एजेंसियों के, अनिष्कारी दुरुपयोग के जरिये, राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध का निरन्तर एवं निष्पक्ष अभियान खुलकर चला रहा है। अनेक राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता जानबूझ कर निशाना बनाये गये हैं तथा अभूत पूर्व तौर-तरीकों से परेशान एवं उत्पीड़ित किये गये हैं।”

इस वक्तव्य में नेताओं ने कहा, “हम इसकी मर्त्सना करते हैं तथा मोदी सरकार की जन-विरोधी, किसान-विरोधी तथा संविधान-विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई को जारी रखने तथा उसे तीव्रता प्रदान करने का संकल्प लेते हैं।”

ज्ञानवापी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। बैंच ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि जिला जज के समक्ष कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है और आदेश 7 नियम 11 के तहत दावे की व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाने वाले आवेदन के परिणाम तक मस्जिद कमेटी की अपील को लम्बित रखना उचित होगा। शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिन्दू श्रद्धालुओं को द्वारा दायर दायीं दावे को यह कहते हुए रिविल जज (सीनियर डिवाजन) से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया कि मुद्दे की “जटिलताओं” और “संवेदनशीलता” को देखते हुए बेहतर यह होगा कि 25 से 30 सालों का अनुभव रखने वाला कोर्ट सीनियर जूडिशियल अधिकारी इस केस को हैंडल करे। शिवलिंग मिलने के बाद यह मस्जिद चर्चा का विषय बनी हुई है और हिन्दू मतावलम्बी इस शिवलिंग की पूजा करने का दबाव बना रहे हैं।

रीट भर्ती 2016 मामले में कैबिनेट सचिव ने राजस्थान मुख्य सचिव को निर्देश दिए

उदयपुर, 21 जुलाई (कास)। रीट भर्ती 2016 में रिक्त करीब 678 पदों के तथ्यात्मक प्रतिवेदनों पर कार्मिक विभाग के अधिकारी तथा उप शिक्षा सचिव के द्वारा पूर्वाग्रहपूर्वक नकारात्मक राय देकर मामले को प्रमित करने को लेकर कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तत्काल आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है।

मामले के एक पीडित अभ्यर्थी ने इस संबंध में गत माह केंद्रीय कैबिनेट सचिव तथा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रकरण में उक्त दोषों अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट की खंडपीठ के जजमेंट व राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एस्पलपी वापसी के प्रशासनिक निर्णय के बावजूद अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने और वास्तविक तथ्यों पर विचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा

■ पीडित अभ्यर्थी ने गत माह केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि, कार्मिक अधिकारी और उप शिक्षा सचिव पूर्वाग्रह प्रस्त नकारात्मक बयान दे रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं।

प्रेषित की थी। पीडित अभ्यर्थी ने उक्त भर्ती के वास्तविक तथ्यों पर कार्मिक विभाग के एक अधिकारी विशेष व स्थानांतरण आदेश के बावजूद अपने पद पर कार्यरत उप शिक्षा सचिव द्वारा इस प्रकरण में भ्रामक नोटिंग तैयार कर कोर्ट जजमेंट को दरकिनार कर सैंकड़ों बेरोजगारों की चयनसूची में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने के इस मामले की जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। मामले में संज्ञान लेते हुए कैबिनेट सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में पीडित अभ्यर्थी के अभ्यावेदन पर तत्काल यथोचित

कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रीट भर्ती वर्ष 2016 प्रकरण लंबित है। राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ व खंडपीठ सभी रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के माफत भरने का आदेश दे चुकी है। गत वर्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने हेतु इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से एस्पलपी भी वापिस ली थी। कहा फंसा है पंच: गत वर्ष भर्ती को नोडल एजेंसी निदेशालय बीकानेर ने सितंबर माह में अंग्रेजी व विज्ञान-गणित के करीब डेढ़ हजार पदों पर अस्थायी

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय अविवाहित महिला को गर्भपात की मंजूरी दी

अविवाहित महिला ने कोर्ट में अनुरोध किया था कि, उसका लिवइंग पार्टनर उसे छोड़ गया है तथा वह अकेली बच्चे का पालन करने में असमर्थ है

नई दिल्ली, 21 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सिर्फ अविवाहित होने के कारण किसी महिला को गर्भपात से नहीं रोका जा सकता।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 वर्षीय एक अविवाहित महिला द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 16 जुलाई के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपना यह फैसला सुनाया। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला को सिर्फ इसलिए अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अविवाहित है। याचिकाकर्ता महिला ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया था, जिसमें उसे अपने 24 सप्ताह के भ्रूण को उसकी (महिला

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में जो कानून है वह एक विधवा या तलाकशुदा महिला को 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।

की) सहमति से संबंध के आधार पर गर्भपात करने की अनुमति का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके लिए बच्चे को पालना मुश्किल था, क्योंकि उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि वह अपने किसान माता-पिता के पांच भाई-बहनों में एक है।

महिला ने कहा था कि अविवाहित होने पर बच्चे को

जन्म देने के कारण सामाजिक बहिष्कार और मानसिक पीड़ा का भी उसे सामना करना पड़ेगा। उसने यह भी कहा था कि वह सिर्फ एक कला महिला को भी शामिल करने के लिए पति के बजाय जरिया नहीं है। लिहाजा वह बच्चे के पालन पोषण

“ई.डी. झूठ ...

चर्चा के लिए तैयार बशर्तें सरकार 11.15 से 11.30 बजे के बीच चर्चा के लिए मान जाए उनकी संसद को चलने देना चाहती है, सरकार की तरफ नहीं जो उन मुद्दों पर सवाल कतराती है, जिनके जवाब नहीं देना चाहती। वरिष्ठ पार्टी नेताओं शशि थरूर, सचिन पायलट और पवन खेड़ा को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किए जाने पर गिरफ्तार किया। कई राज्यों के मुख्यालयों में प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस के प्रदर्शन और कांडीय यात्रा से दिल्ली में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाएगी। शीर्ष न्यायालय अदालत की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 2021 मैडिकलटर्मिनेशनऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए संशोधन में अविवाहित महिला को भी शामिल करने के लिए पति के बजाय “पार्टनर” शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चर्चा के लिए तैयार बशर्तें सरकार 11.15 से 11.30 बजे के बीच चर्चा के लिए मान जाए उनकी संसद को चलने देना चाहती है, सरकार की तरफ नहीं जो उन मुद्दों पर सवाल कतराती है, जिनके जवाब नहीं देना चाहती। वरिष्ठ पार्टी नेताओं शशि थरूर, सचिन पायलट और पवन खेड़ा को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किए जाने पर गिरफ्तार किया। कई राज्यों के मुख्यालयों में प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस के प्रदर्शन और कांडीय यात्रा से दिल्ली में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।